

25 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं. 91 की ओर से श्री रामसिंह गुर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी रफीक मौहम्मद कुरेशी द्वारा पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 02.05.2025 को पेश हो।

*W.S.*

15 वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वाद वादिगण खारिज किया जाता हैं। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।



*W.S.*  
(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी,  
राजवीर सिंह यादव,  
उपखण्ड न्यायाधीश,  
नीमकाथाना (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,  
नीमकाथाना (सीकर)

ठासीन अधिकारी :- राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस

क्रमा न. 268/2023

1. मुकेश कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी गुमानसिंह तहसील नीमकाथाना जिला नीमकाथाना राज.

—वादी

बनाम

1. माडूराम पुत्र बुद्धराम वगैरह

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

स्थित प्रार्थी की ओर से:- श्री रामसिंह गुर्जर एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से:- श्री बनवारी लाल जांगिड़ एडवोकेट

निर्णय

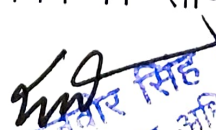
दिनांक:- 02.05.2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाद राजस्व ग्राम मानपुरा पोहो खादरा के भूमि ख0नं0 38, 39 व 44 ता 48 के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्रस्तुत किया है। उक्त भूमियां वर्तमान में मौके पर कृषि भूमि नहीं हैं इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.09.2022 से प्राप्त है। उक्त रिपोर्ट में भूमि की उपयोगिता आवासीय प्रयोजनार्थ होना उचित मानते हुए तहसीलदार नीमकाथाना ने माननीय न्यायालय में

*Rajveer Singh Yadav*  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

एक वाद उनवानी तहसीलदार नीमकाथाना बनाम अणचीदेवी आदि प्रस्तुत कर सहायता चाही हैं कि उक्त भूमियां कृषि भूमि नहीं रही हैं एवं आवासीय उपयोग की होने के कारण कब्जा राज ली जावें। अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमियों का उपयोग आवासीय होने के कारण माननीय न्यायालय को वाद सुनवाई की अधिकारिता नहीं हैं। उक्त भूमियों को आवासीय प्रयोजनार्थ खातेदारान द्वारा काफी समय पूर्व प्रक्रय कर विक्रय लेख एवं इकरारनामों क्रेताओं के हक में तहरीर एवं जिकृत हुई हैं जिनमें भी भूमि की उपयोगिता आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर वादीगण का वाद विरुद्ध तेवादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। वकील प्रार्थी की बहस के प्रारंभ में वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रार्थी के अभिकथनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम मानपुरा 30 खादरा में स्थित होना एवं उनके विभाजन की सहायता चाहने का वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। पटवारी हल्का की कथित रिपोर्ट दिनांक 09.2022 की मद हाजा में दर्ज की गई हैं। वह रिपोर्ट क्योंकि पटवारी का द्वारा तैयार की गई हैं किसके आदेश से तैयार की गई। जबकि उक्त वाद अभी तक पक्षकारान की तामील में ही चल रहा हैं। सीलदार नीमकाथाना द्वारा मद हाजा में वर्णित वाद प्रस्तुत किये जाने वादी को कोई जानकारी नहीं है। कथित वाद से वाद हाजा का कोई किसी प्रकार प्रभावित नहीं हैं। जबकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर्ता की से अभी तक जवाब दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया हैं एवं जब जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में दर्ज आपत्तियों का अंकन किया जाता तब तक प्रार्थना पत्र किसी प्रकार चलने योग्य नहीं हैं। वर्णित भूमियों का अभिलेख राज्य सरकार के अधिनस्थ कारियों द्वारा संधारित किया जाता हैं जिसके अनुसार आज भी भूमियों की उपयोगिता कृषि ही दर्ज हैं एवं कृषि कार्य मौके पर वादी अपने हिस्से की भूमियों में किया जा रहा हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्नी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं जवाब प्रार्थना पत्र


  
 Anand Singh Yadav  
 राज्य सरकार अधिकाारी  
 (स्वीकार)

तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन किया गया तथा बहस कुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रावधानानुसार "Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code (CPC) powers the court to reject a plaint (the document initiating a civil suit) if it fails to meet certain fundamental legal requirements. This provision serves as a gatekeeper, preventing frivolous or unsustainable lawsuits from wasting judicial time and resources. The court can reject a plaint if it lacks a cause of action, is undervalued, not sufficiently stamped, barred by law, not filed in proper jurisdiction, or if the plaintiff fails to comply with other procedural rules"

5 वादग्रस्त आराजी के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांकित 28.05.2022 के आधार पर भूमि की उपयोगिता आवासीय प्रयोजनार्थ होना सिद्ध हुए तहसीलदार नीमकाथाना ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान सरकार अधिनियम बाबत सरकारी भूमि घोषित किये जाने एवं स्थाई ग्राज्जा पेश किया हैं। उक्त तथ्य को वकुलाय उभयपक्ष ने स्वीकार किया अतः वादग्रस्त आराजी की वर्तमान में उपयोगिता आवासीय प्रयोजनार्थ पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी न्यायहित में खारिज किया जाकर वाद वादिगण खारिज किया जाता हैं। पत्रावली क्रमशः 100 ल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले दफतर में सुनाया गया।



  
 (राजवीर सिंह यादव)  
 राजकीय इंसानियत अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नीमकाथाना (सीकर)